भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 723
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में रिक्तियां

723. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल :

श्रीमती माला राय :

श्री अरविंद धर्मापुरी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.12.2024 की तिथि के अनुसार देश में न्यायाधीश-आबादी अनुपात क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों से अब तक देश भर के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की वर्तमान स्थिति और न्याय प्रणाली की कार्यात्मकता पर तत्संबंधी प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिनांक 31.12.2024 की तिथि के अनुसार कर्नाटक सहित उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की राज्यवार कुल संख्या क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने देश में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर रिक्तियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कर्नाटक के विभिन्न न्यायालयों में इन रिक्तियों को भरने और लंबित मामले की दरों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या आपका मंत्रालय कॉलेजियम के समक्ष उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लंबित प्रस्तावों की संख्या का कोई रिकॉर्ड रखता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जो 1210.19 मिलियन थी और 31.12.2024 को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात प्रति मिलियन जनसंख्या लगभग 21 न्यायाधीश बनता है ।

(ख) और (ग) : 04.02.2025 तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों, (कर्नाटक राज्य सहित) का विवरण पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	03.01.2022	02.01.2023	01.01.2024	04.02.2025
1.	उच्चतम न्यायालय	01	06	01	02
2.	उच्च न्यायालय	410	339	330	367

इसके अलावा, 04.02.2025 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों को दर्शाने वाला राज्यवार (कर्नाटक राज्य सहित) विवरण उपाबंध-1 में दिया गया है ।

(घ) और (ङ) : न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होने का एकमात्र कारण न्यायाधीशों का पद रिक्त होना नहीं है । न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या अनेक कारकों के कारण होती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता, अंतर्ग्रस्त

तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है। मामलों के निपटान में विलंब के अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मॉनीटर करने, उनका पता लगाने और समूहबद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है। सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम और विनियम विरचित करती है। मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, कुछ समय-सीमाएं विहित की हैं, जिनका जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया जाना है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है और उच्चतम न्यायालय की 28 अक्टूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामले) के साथ पठित तारीख 6 अक्टूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामले) के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है। प्रक्रिया ज्ञापन के अधीन उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के विचार भी प्राप्त किए जाते हैं। विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी सिफारिशों पर विचार किया जाना होता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशों को तब सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को अग्रेषित किया जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश एससीसी द्वारा की गई है।

सांविधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरे जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या प्रोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की पदसंख्या में वृद्धि के कारण भी उद्भूत होती रहती हैं।

मई 2014 से 04.02.2025 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1013 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। 01.01.2018 से अब तक, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 49 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय में 13 रिक्तियां हैं।

(च) : जी नहीं।

'न्यायपालिका में रिक्तियों' के संबंध में लोक सभा अताराकित प्रश्न संख्या 723 जिसका उत्तर तारीख 07.02.2025 को दिया जाना है के भाग (ख) से (ड) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की रिक्ति।

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	04.02.2025
1	आंध्र प्रदेश	73	83	59	75
2	तेलंगाना	150	115	115	115
3	अरुणाचल प्रदेश	8	10	11	11
4	असम	60	46	24	24
5	बिहार	667	1550	483	483
6	चंडीगढ़	0	1	0	0
7	छत्तीसगढ़	90	139	198	198
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	1	1	1	1
9	दिल्ली	203	89	94	94
10	गोवा	10	10	10	10
11	गुजरात	431	545	535	535
12	हरियाणा	308	208	230	230
13	हिमाचल प्रदेश	16	21	19	19
14	जम्मू - कश्मीर	91	94	43	43
15	लद्दाख	8	7	6	6
16	झारखंड	186	181	199	199
17	कर्नाटक	233	225	219	221
18	केरल	122	91	79	79
19	लक्षद्वीप	0	1	0	0
20	मध्य प्रदेश	372	298	336	336
21	महाराष्ट्र	250	250	250	250
22	मणिपुर	17	10	13	13
23	मेघालय	48	42	42	42
24	मिजोरम	33	33	29	29
25	नागालैंड	10	10	10	10
26	ओडिशा	234	205	200	200
27	पुडुचेरी	17	19	10	10
28	पंजाब	208	212	81	81
29	राजस्थान	331	296	328	342
30	सिक्किम	9	12	12	12
31	तमिलनाडु	272	331	346	346
32	त्रिपुरा	20	20	24	24
33	उत्तर प्रदेश	1173	1247	996	996
34	उत्तराखंड	30	27	28	28
35	पश्चिमी बंगाल	83	83	230	230
36	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह				
	कुल	5764	5428	5260	5292
स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल					